दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 27 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 297

महत्वपूर्ण एवं खास

महाराष्ट्र में बारिशः मरने वालों का आंकड़ा 112 पहुंचा, 100 के करीब लापता

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 112 पहुंच गई है और करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। फिलहाल बारिश थमने के कारण जलस्तर कम हो रहा है और राहत अभियानों ने रफ्तार पकड़ी है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और पुणे इत्यादि जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को रायगढ़ जिले के तालिये गांव का दौरा कर राहत और बचाव अभियानों का जायजा लिया। यहां भूस्खलन के कारण कई घर दब गए थे। अब तक मलबे से 42 शव बरामद हो चुके हैं और 39 लोगों की तलाश जारी है। ठाकरे ने कहा कि यह बड़ी घटना है। सरकार पीड़ितों के पुनर्वास के कदम उठाएगी और हर प्रभावित व्यक्ति की मदद की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया 112 लोगों की मौत हुई है, 99 लापता हैं और 53 लोग घायल हुए हैं। राहत टीमों ने 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कई जगहों पर राहत कैंप लगाए गए हैं।

बलिया सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की हुई मौत

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के चितबड़ागांव क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई जिससे उसपर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी निवासी आदिल (21),समीर(20) व उमरगंज निवासी दिलशाद (20), आदिल (20) बीती देर शाम कार से बलिया से बक्सर जा रहे थे। चितबड़ागांव मोड़ के पास कार मोड़ते समय अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी आदिल व समीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उमरगंज निवासी दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

पंजाब में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले

चंडीगढ़ । अमृतसर में आज से 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। तस्वीरें गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से हैं। एक छात्रा ने बताया, स्कूल खुलने से बहुत खुश हूं और अब मैं चाहती हूं कि स्कूल कभी भी बंद न हो क्योंकि हमारी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है।

मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत

मंदसौर/भोपाल। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की हुई मौत के मामले में सरकार और प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है वहीं शराब बेचने के आरोपी के मकान को जेसीबी से ढहा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, खकराई गांव में रहने वाले लोगों ने शनिवार को शराब पी थी, इनमें से 3 लोगों की शनिवार और रविवार के दौरान मौत हो गई । इस मामले के सामने आने पर राज्य के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया, यह विधानसभा क्षेत्र देवड़ा का है उन्होंने आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामर को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी मनोज पुष्प के निर्देश पर अवैध शराब बेचने वाले योगेंद्र के मकान को ढहा दिया गया है। वहां जेसीबी देर रात को चलाई गई। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा और कहा , शिवराज सरकार में प्रदेश के उज्जैन, मुरैना ,भिंड ग्वालियर के बाद अब मंदसौर जिले के खकराई गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत व कुछ लोगों की गंभीर हालत ही खबर सामने आई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री के क्षेत्र की यही स्थिति है।

संसद का मानसून सत्र : पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा

» संसद के दोनों सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के मानसून सत्र का आज यानी सोमवार से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है, जिसके चलते संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा को सुबह 12 बजे और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू हो गया जिसके चलते इसे पांच बजे तक स्थगित कर दिया गया गया। वहीं, बाद में इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में आज मानसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता है। आज भी नए कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से विपक्ष इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच, सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे।

ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे सांसद राहुल गांधी- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरान कर दिया, जब वह दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। दरअसल, राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन और नए कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता नजर आए। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका था और किसानों के समर्थन में बातें कही गई। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देशभर के किसान पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के किसानों को दबाया जा रहा है। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को काले कानून वापस लेने ही होंगे।

राज्यसभा में भी बरपा हंगामा- राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवाल उठाए गए। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सदन के 90 सदस्यों को उनके नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। मुद्दों में कोरोना टीकों की कमी, टीकाकरण का समयबद्ध समापन, निरंतर महामारी के कारण बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, प्रेस की स्वतंत्रता पर कथित हमले और लक्षद्वीप की स्थिति शामिल हैं।

कोरोना दवाओं की जमाखोरी मामले में गौतम गंभीर को झटका

» सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 दवाओं की अवैध खरीद और वितरण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि लोग दवाओं के लिए चक्कर लगा रहे थे और इस स्थिति में अचानक एक ट्रस्ट कहता है कि हम आपको दवाएं देंगे। बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह सही नहीं है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम भी चीजों पर नजर रखते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट से संपर्क करके उचित राहत का आग्रह करे। फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कैलाश वासदेव ने औषधि और प्रसाधन कानून के तहत इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया। बेंच का रुख देखते हुए गंभीर फाउंडेशन के वकील ने याचिका वापस ले ली।

दिल्ली सरकार के दवा नियंत्रक ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों के लिए फैबीफ्लू दवा के अवैध रूप से भंडारण, खरीद और वितरण का दोषी पाया गया है। अदालत ने भारी मात्रा में दवाओं की खरीद के तरीके नाखुशी जताई थी और कहा था कि उस खास वक्त में जिन लोगों को वास्तव में दवाओं की जरूरत थी उन्हें दवाएं नहीं मिल पाई क्योंकि भारी मात्रा में दवाएं क्रिकेटर से नेता बने गंभीर ने हासिल कर ली थीं। अदालत को सूचित किया गया था कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी दवा एवं प्रसाधन कानून के तहत इस तरह के अपराध का दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

चीन को समझ नहीं पा रही सरकार : राहुल गांधी

» भविष्य में खड़ा होगा संकट

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि सीमा पर चीन की हरकतों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा कि चीन से कैसे निपटा जाए। आज उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि डेमचोक इलाके में भारतीय सीमा के भीतर चीन की सेना ने टेंट लगा दिया है। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा, हमारे तिरंगे की गरिमा में अपनी जान देने वाले प्रत्येक सेनानी को दिल से श्रद्धांजलि। देश की सुरक्षा के लिए आपके व आपके परिवारों के इस सर्वोच्च बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे। जय हिंद।

चीन द्वारा वहां आक्रामकता दिखाने के किसी भी संभावित प्रयास से निपटने के लिए डिवीजन आकार का गठन (लगभग 15,000 सैनिक) को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों से लद्दाख क्षेत्र में ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जवान चीनी आर्मी द्वारा भविष्य में किसी भी कदम का मुकाबले करने के लिए लेह स्थित 14 कोर मुख्यालय की सहायता करेंगे।

कोरोना काल में गांव और शहर दोनों में तेजी से बढ़ी बेरोजगारी

» तीसरी लहर की आशंका से और बढ़ा डर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना के चलते पिछले कुछ वक्त में भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) की रिपोर्ट में इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी हुए हैं।

सोमवार को जारी इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई तक जहां भारत में बेरोजगारी दर 5.98 फीसदी पर थी, वहीं 25 जुलाई तक यह 7.14 फीसदी पहुंच चुकी है। इसमें बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हालांकि महीनावार आंकड़ों में बेरोजगारी की यह दर कुछ कम हुई है। जून में यह 10 फीसदी तक थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ है, जिससे इसमें कमी आई है। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। वहीं तीसरी लहर की आशंका आगे के लिए भी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है।

व्यापारिक गतिविधियों में भी कमी- सीएमआई श्रमिक बाजार पर निगाह रखता है। इसके मुताबिक पिछले हफ्ते शहरी बेरोजगारी दर का आंकड़ा 8.01 पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते यह 7.94 फीसदी पर था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.75 पर पहुंच चुकी है, जो कि पिछले हफ्ते काफी नीचे 5.1 पर थी। वहीं सोमवार को ही व्यापार के फैलाव से जुड़ा आंकड़ा भी जारी हुआ है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजंप्शन इंडक्शन (एनआईबीआरआई) की तरफ से जारी आंकड़े गिरकर 95.3 पर पहुंच गए हैं, जो पिछले हफ्ते 96.4 पर थे। इन आंकड़ों में गिरावट व्यापारिक गतिविधियों में कमी को दिखाता है। इन आंकड़ों को तैयार करने वाली संस्था के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी ये आंकड़े ठीक थे। हालांकि महामारी से पहले की तुलना में इनमें 4.7 फीसदी की गिरावट आ चुकी थी।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया : जी. किशन रेड्डी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और प्रशाद की अपनी योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सहित देश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति और उसकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। योजनाओं के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और उनकी मंजूरी, प्रस्तावों की प्रस्तुति, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के उनके अनुपालन, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, फंड की उपलब्धता और पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोग के अधीन दी जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने 2015-16 में सिंधुदुर्ग तटीय सर्किट (शिरोदा बीच), सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), देवगढ़ (किला और समुद्र तट), मितभाव, टोंडावली, मोसेहमद तथा निवती किला के महाराष्ट्र तटीय सर्किट विकास को 19.06 करोड़ रुपये की तथा 2018-19 में वाकी-अदासा-धापेवाड़ा-परदसिंह-छोटा ताज बाग-तेलखंडी-गिराड के आध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिए 54.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 में त्र्यंबकेश्वर के विकास के लिए 37.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों, हिल स्टेशनों, समुद्र तटों, वन्य जीवन, विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों और मंदिरों सहित एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा देता है। अपनी जारी गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में देश में पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान चलाता है। मंत्रालय अपनी वेबसाइटों और समय-समय पर तैयार की गई प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से पर्यटन स्थलों और उत्पादों को भी बढ़ावा देता है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

संसद ने दी राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है।

लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 पेश किया। सदन ने विभिन्न विषयों पर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक मार्च महीने में राज्य सभा में पारित हो चुका है।

विधेयक के दस्तावेज के अनुसार, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संस्थान कई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। इसके तहत आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं से और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रबंध की ऐसी अन्य शाखाओं में ज्ञान के प्रसार का उपबंध किया गया है। इसमें परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य ज्ञान संबंधी विशेष उपाधियां या पदवियां तथा मानद डिग्रियां प्रदान करने का उपबंध है।

एमपी-सीजी के कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थितकृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार गांव-गरीब-किसान-किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। देशभर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए हैं। हर सप्ताह मंत्रालय में इसकी प्रगति के लिए बैठकें होती है। इसी तरह, 6,850 करोड़ रू. के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं, ये कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 86 प्रतिशत छोटे-मझौले किसान इनके माध्यम से और मजबूत होंगे, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कोरोना के संकटकाल में भी केवीके के वैज्ञानिक, सूचना-संचार तकनीकों एवं कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों द्वारा लाभ पहुंचा रहे है, जो सराहनीय है।पशु धन एवं मछली पालन के विकास के लिए भी हमारे केवीके पूरे जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं तथा कृषि व सभी सम्बद्ध क्षेत्रों की सतत प्रगति व किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।वर्तमान में 723 केवीके, आईसीएआर की इकाइयों, गैर सरकारी संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे है, जिनसे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। अटारी, जबलपुर के तहत म.प्र. व छग में 81 केवीके हैं। 81 में से 28 छग में हैं, जिनमें से 7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।यहां तमाम चुनौतियों के बीच भी केवीके सुचारू काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने सभी वैज्ञानिकों व अन्य स्टाफ को बधाई-शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये सभी विंग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। केवीके की टीमें जिलों व गांवों तक बखूबी काम कर रही है और कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में तकनीकी समर्थन व सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्त्रोत के रूप में अहम भूमिका का निर्वाहन कर रही है।

तोमर ने कहा कि देशभर के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से दलहन, गेहूं व सोयाबीन तथा छत्तीसगढ़ से धान की पैदावार का महत्वपूर्ण योगदान है। संतोष की बात है कि केवीके के माध्यम से क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन व सीड हब द्वारा दलहन की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में सोयाबीन फसल के 60 लाख हेक्टेयर में से करीब 35 लाख हेक्टेयर पर ऊंची क्यारी (रेज्ड बेड) तकनीक का उपयोग करके जल संरक्षण द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा रही है, वहीं कड़कनाथ मुर्गी पालन केवीके के प्रयासों से 25 राज्यों में हो रहा है और विदेशों से भी मांग है।